

कई देश विदेशी फंड नियंत्रित करते हैं

एफसीआरए बिल पर भारत का जवाब- यह हमारा आंतरिक मामला है

नई दिल्ली, 7 अगस्त. केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर स्पष्ट किया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी अन्य देश को इस विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही. उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल हैं, विदेशी फंडिंग और विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून और नियामकीय व्यवस्थाएं लागू करते हैं. सरकार की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद रिले एम. मूर की उस सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एफसीआरए संशोधन विधेयक को ईसाइयों के खिलाफ बताया था. मूर ने 4 अगस्त को सोशल मीडिया मंच



एक्स पर लिखा था कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध

इस विधेयक को लेकर कुछ धार्मिक संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं ने चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं में छेदी बुटियां की स्थिति में कठोर कार्रवाई की आशंका बनी रह सकती है. हालांकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रस्तावित संशोधन पूर्ण प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं होगा. संसदीय स्थिति के अनुसार, यह एक सामान्य विधेयक है, जिसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी.

था और इस पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा प्रस्तावित है. सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक पर होने वाली चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं. सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र और धन के उपयोग का स्पष्ट विवरण देना होगा. साथ ही, विदेशी अंशदान का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकेगा. एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त, निरस्त या रद्द हो जाता है, तो विदेशी अंशदान से अर्जित उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को सौंपी जा सकेगी.

जमात गठबंधन का सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन

ढाका, 7 अगस्त. बंगलादेश में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 विपक्षी दलों के गठबंधन ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों और ढाका में एक बड़ी रैली करने की घोषणा की है जिसका

- ▶ **बांग्लादेश में विपक्ष का दबाव बढ़ा**
- ▶ **नवंबर में ढाका में बड़ी रैली**

उद्देश्य बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह जुलाई के 'नेशनल चार्टर' और जनमत संग्रह के फैसले को लागू करनके के साथ ही ईधन, गैस एवं बिजली की कीमतों कम करे और देश में चल रहे महंगाई के

संकट का समाधान करे.

ढाका के पलटन इलाके में मुकंगन में गुरुवार को धरने के दौरान गठबंधन के प्रमुख और जमात अमीर शफीकुर रहमान ने इन कार्यक्रमों की घोषणा की. ये कार्यक्रम गठबंधन द्वारा बताये गये मुद्दों पर केंद्रित हैं जिसमें ईंधन और गैस का संकट, बिजली के फर्जी बिल, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें शामिल हैं. शफीकुर के अनुसार, यह आंदोलन बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने, सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी संस्थानों पर संकीर्ण दलीय नियंत्रण को खत्म करने

सीएम विजय की पत्नी ने वापस ली तलाक की अर्जी



चेन्नई, 07 अगस्त. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के निजी जीवन से जुड़ा बहुचर्चित तलाक विवाद अब अदालत में खत्म हो गया है. उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने चेंगलपट्टु फैमिली कोर्ट ज् में दाखिल तलाक की अजीज शुक्रवार को वापस ले ली.

संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुईं. उन्होंने

जज सुजाता को अपनी याचिका वापस लेने की जानकारी दी. इसके बाद जज ने करीब 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की और उनकी अजीज स्वीकार करते हुए तलाक की कायज्वाही समाप्त कर दी. संगीता ने इसी साल फरवरी में तलाक की याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने विजय पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि अप्रैल 2021 में उन्हें अपने पति के एक अभिनेत्री के साथ संबंधों के बारे में जानकारी मिली. इस घटना के बाद उन्हें मानसिक परेशानी हुई.

जेन जी का मन टटोलेगी योगी सरकार

लखनऊ, 07 अगस्त. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच युवाओं को लेकर सियासी रणनीति तेज हो गई है. योगी सरकार अब जेन जी यानी नई पीढ़ी के युवा मतदाताओं की नब्ज टटोलने की तैयारी में है.

इसके लिए सरकार 16 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र युवा आयोग गठित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. प्रस्तावित आयोग के जरिए युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को समझने के साथ उन्हें सरकार की नीतियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

युवा वगज़ किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन

- ▶ **युवाओं पर योगी सरकार का फोकस**
- ▶ **स्वतंत्र आयोग करेगा निगरानी**

आंदोलनों में बदल चुका है. हाल ही में पेपर लीक के मुद्दे पर हुए छात्र आंदोलनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा वगज़ की राजनीतिक ताकत चर्चा में रही. उत्तर प्रदेश में बड़ी युवा आबादी को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भी युवा मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है. विपक्षी दल युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रस्तावित आयोग का दायरा 16 से 35 वर्ष की युवाओं तक हो सकता है.

पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे



घटनाक्रम के अलावा राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों और संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होने की अटकलें हैं. शिंदे की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब उड़व बालासाहेब ठाकरे गुट के

इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी. शिवसेना के कुछ सांसदों ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी. इन बैठकों में सांसदों के निवाज्जन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई थी. मुंबई में सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है. प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति और राजनीतिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उनकी सुनेत्रा पवार के साथ मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इस बैठक के एजेंडे या भविष्य की किसी राजनीतिक रणनीति से जुड़े होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को दी मंजूरी

नई दिल्ली. दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के साथ राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. बिल के कानून बनने से पहले इसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा. विधानसभा से पारित होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी देकर राजधानी में निजी विश्वविद्यालय लाने का रास्ता साफ कर दिया है.

▶ प्रथम पृष्ठ का शेष ... ◀

एनडीए के 45 नए सांसदों से मिले पीएम मोदी

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को संसद की कार्यवाही में सक्रिय और साथैक भागीदारी की सलाह दी. उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां स्वस्थ चर्चा और व्यवस्थित कार्यवाही होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने लगातार होने वाले हंगामे पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे नए सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पाता. उन्होंने सांसदों से इतिहास का अध्ययन करने, पूरी तैयारी के साथ बहस में भाग लेने तथा अपने-अपने राज्यों और संसदीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों से जुड़े मामलों में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए कार्य करने पर जोर दिया. लोकसभा में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के तहत तुणमूल कांयेस से अलग हुए 20 सांसद नेशनल सिटिजनस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होकर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं. वहीं, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के छह सांसद भी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ आ चुके हैं. मानसून सत्र के दौरान इन सांसदों की लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की गई है. उपलब्ध संसदीय आंकड़ों के अनुसार, इन राजनीतिक बदलावों के बाद लोकसभा में एनडीए की संख्या बढ़कर 318 तक पहुंच गई है. वर्तमान में तीन लोकसभा सीटें रिक्त हैं, जिसके आधार पर सदन की प्रभावी सदस्य संख्या 540 मानी जा रही है. इस स्थिति में संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के 360 के आंकड़े से एनडीए अभी 42 सांसद पीछे है. वहीं राज्यसभा में भी गठबंधन का संख्या बल बढ़ा है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े से अभी 11 सदस्यों की कमी बनी हुई है.

जनता के दरवाजे पर मोहन सरकार

मुख्यमंत्री ने एएसडीएम चौरई, संबंधित तहसीलदार एवं पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए. नागरिकों को शिकायत करने की नौबत नहीं आना चाहिए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने राजस्व, नल-जल, ऊर्जा, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत करने की नौबत नहीं आनी चाहिए. प्रत्येक प्रकरण का निश्चित समय-सीमा में पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने डॉन-आउट बच्चों को पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलाने, सभी शिक्षकों की शत-प्रतिशत ई-अटेंडेस सुनिश्चित करने तथा सायबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है तथा प्रत्येक अधिकारी को जनसेवा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह कार्यशैली अपनानी होगी.

मैं आऊंगा होम-स्टे पर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सनोत नागवंशी ने ग्रामीण पर्यटन एवं होम-स्टे मॉडल की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शासन से सख्तीया प्राप्त हुई है. वर्तमान में वे दो कमरों का होम-स्टे संचालित कर रहे हैं, जिसे मेक माय ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सूचीबद्ध किया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मैं जरूर आपके होम-स्टे पर आऊंगा.

आज का इतिहास

1967- आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

1973- दक्षिण कोरियाई राजनीतिज्ञ किम डेए-जुंग को केसीआईए ने टोक्यों में अपहरण किया गया।

1988- अफ़ग़ानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई।

1990- इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम ने घोषणा की कि उसने कुवैत को 19वें प्रांत के रूप में अपने देश का भाग बना लिया है।



- ▶ **जन्म आधार पर नागरिकता सीमित करने का आदेश**
- ▶ **बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने का आदेश**

वॉशिंगटन, 07 अगस्त. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने

नेहा बोरा ने लगाया स्याही

फेंकने का आरोप

रांची, 07 अगस्त. झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय छात्र संघ की अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुद पर स्याही फेंके जाने का आरोप लगाया है.

नेहा बोरा ने दावा किया कि बिरसा मुंडा स्टेडियम से माचर निकाले जाने के दौरान 26 वर्षीय अमरनाथ पांडेय नाम के एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंकी. उनके मुताबिक, प्रदर्शन में



मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. नेहा ने बताया कि वह अन्य साथियों के साथ माचर के दौरान खड़ी थीं, तभी अमरनाथ पांडेय नाम के युवक ने उन पर स्याही फेंक दी.

महबूबा मुफ्ती की बेटी पर एफआईआर

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प अब कानून-व्यवस्था में बदल गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. मामला 4 अगस्त को हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था. इसी दौरान इल्तजा मुफ्ती और पुलिस अधिकारियों के बीच कथित तौर पर तीखी बहस हुई.

अमित शाह बोलेंगे तो सुन नहीं पाओगे

नई दिल्ली, 07 अगस्त. विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर नारेबाजी की है. जिसके चलते दोनों सदनों

- ▶ **विपक्ष पर रिजिजू का हमला**

की कायज्वाही स्थगित कर दी गई. विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में 'अमित शाह सदन में आओ' के नारे लगाए. जिस पर संसदीय कायज्त्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा विपक्ष के सांसद सदन में आते हैं



इसलिए यह नाटक बंद करना चाहिए .

और नारेबाजी करके चले जाते हैं. लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा. हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने कहा 'ये लोग (विपक्ष) के सांसद हर दिन सुबह आते हैं. सदन में गृहमंत्री

रिजिजू ने कहा 'विपक्ष किसी को आदेश नहीं दे सकता. आप निदेज्ज नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है. यह तय करना सरकार का काम होता है, आसन यह तय करता है. लेकिन यह लोग सदन को बाधित करके लगातार देश को गुमराह करने में लगे हैं.

अमित शाह का नाम लेकर नारे लगाते हैं और हंगामा करके गायब हो जाते हैं. लेकिन मैं बताता चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह-सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं. वह दिनभर संसद में ही रहते हैं.

होर्मुज पर ईरान की नई चाल

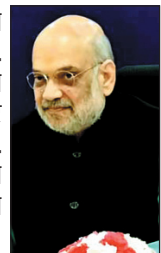
तेहरान, 07 अगस्त. ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिका, इजरायल तथा अन्य दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने पर प्रतिबंध लगाने लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है और मौजूदा समय में ईरानी सांसद इसकी समीक्षा कर रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर ईरानी संसद इस प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर देती है, तो यह होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में सुरक्षा, नेविगेशन और आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार करेगा. ग्याह अनुच्छेद वाले इस शुरुआती प्रस्ताव से ईरानी अधिकारियों को समुद्री ट्रैफ़िक पर ज्यादा अधिकार मिलेंगे.

हस्तियों के ट्वीट



भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत न सिर्फ इसकी विविधता में है, बल्कि उन कुशल हाथों में भी है जो इसे संजोकर रखते हैं. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, हम अपने उन प्रतिभाशाली बुनकरों का सम्मान करते हैं जिनकी कारीगरी हमारी समृद्ध वस्त्र-विरासत को पीढ़ियों से जीवित रखे हुए है. आइए, हम अपने बुनकरों का समर्थन करें और भारत की विरासत को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल तक ले जाने में मदद करें.

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव टैगोर की जयंती पर नमन करते हुए अपने विचार व्यक्त किये. उन्होंने सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि कविगुरु गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन. गुरुदेव टैगोर ने अपनी लेखनी से भारत की आत्मा को स्वर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संसार किया.



प्रदर्शन

लोस में नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर विरोध, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

राहुल गांधी के आवास के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

नई दिल्ली, 7 अगस्त. अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर कुछ साधु-संतों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन की कोशिश की.

प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शनकारियों में कुछ

साधु-संत भी शामिल थे. पुलिस ने उन्हें आवास की ओर बढ़ने से रोका और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की.

घटना के दौरान इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया और आवास के आसपास निगरानी भी तेज कर दी गई. यह विरोध अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले पर हाल में हुई राजनीतिक टिप्पणियों के बाद सामने आया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया गया और धार्मिक आस्था से जुड़े विषय को संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया गया.



कल प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद

प्रयागराज. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रयागराज देश की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, नेट हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है. उन्होंने कहा कि प्रयागराज देश का वह शहर है, जहां सबसे अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यहां का हर छात्र जानता है कि व्यवस्था ईमानदार नहीं रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, वर्षों तक इंतज़ार और जवाबदेही के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या उस व्यवस्था की है, जो उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं करती.